RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®
इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 06 से 12 सितम्बर 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 12 | अंक-57 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

त्योहारों पर सरकार का तोहफ़ा: जीएसटी राहत से घर-घर में खुशियां

रोज़मर्रा के सामान होंगे सस्ते और जीवन बीमा में राहत

भोपाल: जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए "जीएसटी दीवाली उपहार" की घोषणा की है, जिसमें रोजमर्रा के सामानों पर कर दरें कम की गई हैं और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सुधार मध्यम वर्ग को राहत देंगे और अर्थव्यवस्था को गति देंगे। बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो त्योहारों से पहले खरीदारी को बढ़ावा देंगे। अनुमान है कि इससे 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उपभोक्ता मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

जीएसटी दरों के अनुसार आइटमों का वर्गीकरण

जीएसटी सुधारों में विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं पर दरें कम की गई हैं। यहां दरों के अनुसार आइटमों का संगठन है:

0% जीएसटी (पूरी तरह मुक्त):

खाद्य आइटम: छेना, पनीर, ब्रेड, भारतीय रोटियां (चपाती, नान, परांठा), दूध, दही, अनाज, सब्जियां, फल।

अन्य: जीवन रक्षक दवाएं (कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग के लिए), सैनिटरी नैपकिन, किताबें, समाचार पत्र।

बीमा: व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (पहले 18%)। यह बदलाव 10 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारकों को प्रभावित करेगा, जो सालाना 15,000 करोड़ रुपये की बचत करेगा।

5% जीएसटी (पहले 12% या 18% से कम):

व्यक्तिगत देखभाल: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, कंडीशनर।

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर (1.5 टन तक), टीवी (32 इंच तक), रेफ्रिजरेटर (300 लीटर तक)।

परिवहन: छोटी कारें (1200 सीसी तक), मोटरसाइकिल (350 सीसी तक)।

अन्य: चाय, कॉफी, मसाले, पैकेज्ड फूड आइटम। यह श्रेणी एमएसएमई को लाभ देगी, जो इन उत्पादों का बड़ा हिस्सा बनाते हैं।

18% जीएसटी (पहले 28% से कम):

हाइब्रिड वाहन: पेट्रोल-सीएनजी हाइब्रिड कारें।

लक्जरी आइटम: बड़े टीवी (32 इंच से अधिक), बड़े रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन।

अन्य: बिस्कुट, चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स। यह कमी पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देगी।

प्रभाव और विश्लेषण

ये बदलाव 400 से अधिक आइटमों को प्रभावित करेंगे, जो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लिए हैं। बीमा पर राहत से स्वास्थ्य कवरेज बढ़ेगा, जबकि सस्ते सामान से खपत बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जीएसटी 2.0 की शुरुआत है, जो कर प्रणाली को सरल बनाएगा। हालांकि, राज्यों को राजस्व हानि की चिंता है, लेकिन केंद्र ने मुआवजा का आश्वासन दिया है। लंबे समय में, यह अर्थव्यवस्था को 5-6% की वृद्धि दे सकता है।

निष्कर्ष

यह दीवाली उपहार उपभोक्ताओं को खुशी देगा और छोटे व्यवसायों को समर्थन करेगा, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए।

भारत अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के बीच व्यापार नेटवर्क को व्यापक करने की रणनीति अपनाई है, कतर से ऑस्ट्रेलिया तक सौदों पर नजर

वैश्विक बाजारों में निर्यात विविधता के लिए नई रणनीति

नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करने के बाद भारत ने अपने व्यापार नेटवर्क को व्यापक करने की रणनीति अपनाई है, जिसमें कतर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कतर और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों से मुलाकात की, जो इस समय भारत के साथ व्यापार समझौतों के अभाव में हैं। यह कदम अमेरिका के साथ व्यापारिक अनिश्चितता के बीच उठाया गया है, जहां 27 अगस्त 2025 से भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू हो गया है।

भारत का लक्ष्य अपने निर्यात बाजारों को विविधता प्रदान करना और दवा, रसायन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक विकास में 18% का योगदान देता है और यूरोपीय संघ, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक समझौतों पर काम कर रहा है। यूएई, यूके और ईएफटीए ब्लॉक के साथ पहले से समझौते हो चुके हैं। कतर के साथ जल्द ही व्यापार वार्ता शुरू होने की उम्मीद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक समझौते को आगे बढ़ाने में रुचि दिखा रहा है।

हालांकि, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार सौदे पर भी बातचीत जारी है, लेकिन रूस से तेल खरीद को लेकर तनाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति भारत को वैश्विक व्यापार में स्थिरता प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके लिए घरेलू उद्योगों को वैश्विक मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। निर्यात में विविधता लाने से छोटे और मध्यम उद्यमों को भी लाभ हो सकता है।

यह स्पष्ट है कि भारत अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों का जवाब वैश्विक सहयोग बढ़ाकर दे रहा है। यह कदम भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

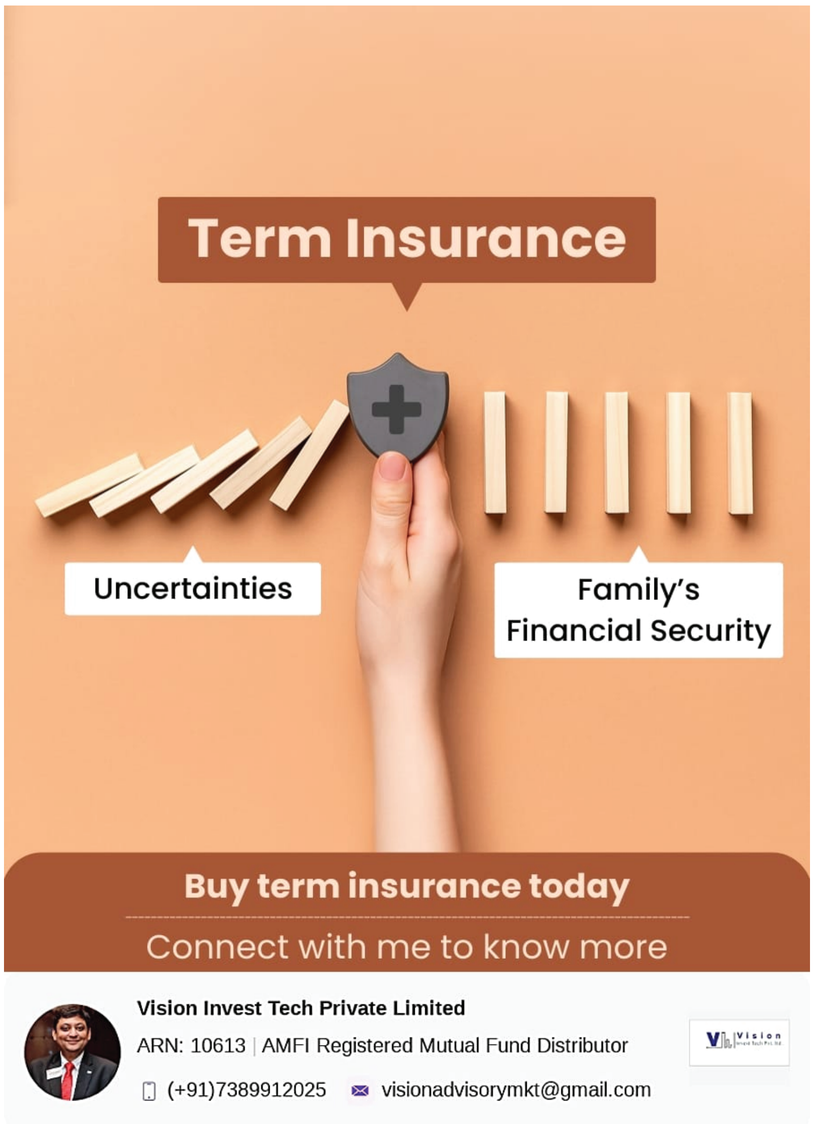

एसबीआई का राज्यों को आश्वासन: पीएम मोदी के दीवाली जीएसटी उपहार से न डरें, आप अभी भी लाभ में रहेंगे

कर संरचना में बदलाव से राज्यों को होगी आर्थिक मजबूती

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को एक शोध रिपोर्ट में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित जीएसटी संरचना में बदलाव, जो दीवाली का उपहार माना जा रहा है, से राज्यों को अभी भी आर्थिक लाभ होगा। कुछ राज्यों ने चिंता जताई थी कि कर दरों में कमी से राजस्व हानि हो सकती है, लेकिन एसबीआई का कहना है कि राजस्व बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था के कारण वे नेट गेनर बने रहेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी संग्रहण को केंद्र और राज्यों के बीच 50-50% के अनुपात में बांटा जाता है, और कर वितरण के तहत केंद्र का 41% हिस्सा राज्यों को वापस मिलता है। इससे हर 100 रुपये के संग्रहण में राज्यों को लगभग 70.5 रुपये प्राप्त होते हैं। एसबीआई ने अनुमानलगाया कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों को एसजीएसटी से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये और कर वितरण से 4.1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जो उन्हें लाभ में रखेगा।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दीवाली तक लागू होंगे, जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर कम होंगे। यह कदम उपभोक्ताओं और एमएसएमई को राहत देने के लिए है, लेकिन कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने 2 लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई थी। एसबीआई का सुझाव है कि मुआवजा कोष के अधिशेष का उपयोग कर दरों में बदलाव से होने वाले नुकसान को पूरा किया जा सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि कर दरों में कमी से अल्पकालिक राजस्व में 3-4% की गिरावट (लगभग 60,000 करोड़ रुपये सालाना) हो सकती है, लेकिन लंबे समय में कर संग्रहण में 5-6% की वृद्धि होगी। यह सुधार कर प्रणाली को सरल बनाएगा और अनुपालन बोझ को कम करेगा, जिससे कर आधार बढ़ेगा। यह देखना बाकी है कि क्या राज्यों की चिंताएं पूरी तरह दूर होंगी या इस नीति का लाभ सभी के लिए होगा।

India Pioneers Round-the-Clock Renewable Energy at Unmatched Global Rates: Piyush Goyal

Sustainability Drive Positions India as G20 Leader

New Delhi: Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has hailed India's emergence as a global leader in renewable energy, offering round-the-clock clean power at rates unmatched worldwide. Speaking at the 20th Global Sustainability Summit on September 2, 2025, Goyal highlighted that India provides 24-hour renewable energy at Rs 4.60 to Rs 5.00 per kWh, roughly five cents, a price he described as unparalleled globally.

This achievement stems from India's aggressive push to meet sustainability goals, with 50% of its renewable energy capacity already installed, surpassing targets ahead of schedule. The country aims to reach 500 GW by 2030, leveraging "Make in India" products and self-reliant manufacturing. Goyal credited transparent bidding processes for reducing solar power costs from Rs 7-8 to Rs 2.41 per unit, enabling this competitive pricing. He emphasized that pursuing coal and renewables simultaneously ensures energy security without compromising sustainability.

India's success is attributed to Prime Minister Narendra Modi's leadership at COP21, uniting the global south and securing commitments from developed nations. However, Goyal criticized the latter for failing to deliver the promised $100 billion annual climate finance. With India contributing 18% to global growth and aiming to become the world's third-largest economy, this renewable energy model underscores its focus on inclusive growth.

The initiative also calls for innovation in water harvesting and energy efficiency, urging startups to contribute. While this positions India as a G20 frontrunner, challenges like infrastructure and global supply chain resilience remain. The model could inspire other nations, but its long-term viability hinges on sustained investment and policy support.

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट ऐवेन्युस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले क्या याद रखें और गलतियाँ से बचें

सही जानकारी जुटाएँ

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से पहले अपनी सभी आय स्रोतों की सटीक जानकारी एकत्र करें। इसमें वेतन, किराए से आय, ब्याज, पूंजीगत लाभ और व्यवसायिक आय शामिल है। गलती से आय छिपाने से नोटिस आ सकता है, इसलिए सभी दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश रसीदें तैयार रखें।

सही ITR फॉर्म चुनें

हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म है। सैलरीड लोगों के लिए ITR-1, व्यवसायियों के लिए ITR-3 और विदेशी आय वालों के लिए ITR-2 उपयुक्त है। गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए अपनी आय के हिसाब से फॉर्म चुनें।

समय सीमा का ध्यान रखें

ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है (गैर-ऑडिटर के लिए), लेकिन अगर आप देरी करते हैं तो पेनल्टी 1,000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है। जल्दी दाखिल करने से सुधार का मौका भी मिलता है।

डिजिटल सबमिशन और सत्यापन

ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करें और रिटर्न को Aadhaar OTP या ई-वेरिफिकेशन से सत्यापित करें। ऑफलाइन सत्यापन भूलने से रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।

गलतियाँ से बचें

- गलत PAN या आधार नंबर डालने से बचें।
- छूट का गलत दावा (जैसे सेक्शन 80C में 1.5 लाख से ज्यादा) से बचें।
- TDS और एडवांस टैक्स का मिलान न करने से परेशानी हो सकती है।

निष्कर्ष

ITR दाखिल करना आसान है अगर आप सावधानी बरतें। सही जानकारी, समय और सत्यापन से न केवल पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि कर योजना भी बेहतर होगी।

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

Hyundai Motor India Sees 4.23% Sales Decline to 60,501 Units in August

Export Surge Counters Domestic Slump Amid Global Ambitions

Bhopal: Hyundai Motor India Limited reported a 4.23% drop in total sales for August 2025, recording 60,501 units compared to 63,175 units in the same month last year. The decline reflects a challenging domestic market, with domestic sales falling 11% to 44,001 units from 49,525 units, driven by weaker demand for models like the i10 and i20. This dip suggests shifting consumer preferences or economic pressures impacting the auto sector.

Despite the domestic setback, exports provided a bright spot, surging 21% to 16,500 units from 13,650 units, underscoring Hyundai's growing global presence. The company aims to establish India as its largest export hub outside South Korea, a goal gaining traction with 1,18,840 units exported from January to August 2025. Tarun Garg, Whole-time Director and Chief Operating Officer, emphasized the "Make in India" initiative, highlighting the synergy of advanced manufacturing and skilled labor to support the "Atmanirbhar Bharat" vision.

The mixed performance raises questions about domestic market resilience, especially with festive season demand yet to kick in. Some analysts attribute the slump to rising vehicle costs and competition, while others see it as a temporary lull. The export growth, however, signals Hyundai's strategic shift toward international markets, potentially offsetting local challenges. The industry watches whether upcoming policy changes or festive sales might reverse the trend. Hyundai's focus on exports could redefine its role in India's automotive landscape, though sustaining domestic momentum remains critical.

TVS Motor Reports 30% Sales Surge Year-Over-Year in August

Robust Domestic and Export Growth Fuels Record Performance

Bhopal: Chennai: TVS Motor Company celebrated a remarkable 30% year-on-year (YoY) sales increase in August 2025, reaching a record 5,09,536 units compared to 3,91,588 units in August 2024. This surge highlights the company's strong market presence and strategic focus on diverse segments. Two-wheeler sales soared 30% to 4,90,788 units from 3,78,841 units, with domestic sales rising 28% to 3,68,862 units. Motorcycles grew 30% to 2,21,870 units, while scooters jumped 36% to 2,22,296 units, reflecting shifting consumer preferences toward urban mobility.

The three-wheeler segment also shone, with a 47% YoY increase to 18,748 units, driven by demand for versatile vehicles. Exports further boosted the figures, climbing 35% to 1,35,367units from 99,976 units, underscoring TVS's growing global footprint. This performance marks the first time the company crossed the five-lakh-unit milestone, a testament to its innovation and adaptability.

While the growth is impressive, some question whether it masks underlying challenges, such as supply constraints for electric vehicle (EV) magnets, which limited EV sales to a modest 1.4% rise to 25,138 units. Critics suggest the surge may reflect pent-up demand rather than sustainable momentum, especially with festive season uncertainties looming. Nonetheless,TVS's balanced portfolio across internal combustion engine (ICE) and EV segments, alongside robust export gains, positions it as a resilient player.

The industry watches whether this momentum will carry into the festive season. TVS's ability to maintain supply chains and meet diverse market needs will be key to sustaining this growth trajectory.

Ashok Leyland Registers 5% Sales Growth to 15,239 Units in August

Steady Domestic Rise and Export Gains Drive Commercial Vehicle Success

Chennai: Ashok Leyland, a leading commercial vehicle manufacturer, reported a 5% year-on-year increase in total sales for August 2025, reaching 15,239 units compared to 14,463 units in August 2024. The growth reflects a resilient demand in the domestic market, where sales rose 2% to 13,622 units from 13,347 units, driven by steady demand for medium and heavy commercial vehicles (M&HCVs) and buses.

The company's performance was bolstered by a robust bus segment, though truck sales showed mixed results. Exports contributed to the uptick, helping offset a modest domestic gain. Despite the positive sales figures, the company's shares dipped slightly, trading at ₹126.70 on the Bombay Stock Exchange, down 0.16%, suggesting investor caution amid broader market trends.

This growth aligns with India's improving infrastructure and freight demand, though some analysts question its sustainability given global supply chain challenges. Ashok Leyland's focus on expanding its product range and export markets appears to be paying off, positioning it well in the competitive commercial vehicle sector.

The industry awaits further data to assesswhether this momentum will hold through the festive season. The company's ability to navigate economic uncertainties will be key to sustaining this upward trend.

आरबीआई ने पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी के यस बैंक चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी

अनुभवी केंद्रीय बैंकर की नियुक्ति से बैंक को मिलेगी मजबूती

भोपाल: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यस बैंक के अंशकालिक गैर-कार्यकारी चेयरमैन के रूप में पूर्व डिप्टी गवर्नर राम सुब्रमण्यम गांधी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक प्रभावी होगी। 37 साल के केंद्रीय बैंकिंग अनुभव वाले गांधी ने 2014 से 2017 तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवा दी थी।

यस बैंक ने मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि आरबीआई ने 1 सितंबर 2025 के पत्र के माध्यम से इस पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। गांधी की नियुक्ति से बैंक को वित्तीय क्षेत्र में मजबूती और नीति निर्धारण में गहराई मिलने की उम्मीद है। उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) में तीन साल का कार्यकाल भी पूरा किया है और बैंकिंग टेक्नोलॉजी संस्थान (आईडीआरबीटी) के निदेशक के रूप में भी काम किया है।

यह कदम यस बैंक के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय चुनौतियों से जूझता रहा है। गांधी की विशेषज्ञता और अनुभव से बैंक के शासन और विकास में सुधार की उम्मीद है। बाजार में यस बैंक के शेयरों में इस खबर के प्रभाव को लेकर सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियुक्ति बैंक की भविष्य की स्थिरता के लिए एक मजबूत कदम हो सकता है।

Ajay Seth Assumes IRDAI Chairmanship After Five-Month Vacancy

Experienced Economist Steps in to Tackle Insurance Sector Challenges

New Delhi: Ajay Seth, a seasoned 1987-batch IAS officer from the Karnataka cadre, has taken charge as the Chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) following a five-month gap. The appointment, cleared by the Appointments Committee of the Cabinet on July 24, 2025, became effective on September 1, 2025, filling the void left after Debasish Panda's tenure ended in March 2025.

Seth, who retired as the Department of Economic Affairs Secretary in June 2025, brings over three decades of experience in economic policy and regulatory reforms. His prior roles include shaping India's post-pandemic fiscal policies, issuing sovereign green bonds, and overseeing infrastructure financing. This expertise positions him to address pressing issues in the insurance sector, including the implementation of a risk-based capital framework, the launch of the Bima Sugam digital marketplace, and the proposed Insurance Amendment Bill, 2025, which seeks to allow 100% foreign direct investment.

The five-month leadership gap had stalled key reforms, raising concerns about policyholder protection and sector growth. Seth's appointment is seen as a strategic move to restore momentum, especially as the industry grapples with slowing growth, health insurance disputes, and mis-selling issues. Industry experts anticipate his focus on transparency and financial soundness will bolster IRDAI's credibility.

However, challenges loom large, with the sector awaiting legislative approvals and global competitiveness pressures. Seth's tenure, set for three years or until he turns 65, will be critical in steering India's underpenetrated insurance market toward long-term stability. His leadership is expected to balance regulatory rigor with industry support, marking a pivotal chapter for IRDAI.

AJAY SETH

Government Extends Semiconductor Project Support, Expands Design-Linked Incentives: IT Secretary

Boost to Domestic Industry Amid Global Chip Race

New Delhi: The Indian government has reaffirmed its commitment to the semiconductor sector, with Electronics and IT Secretary S Krishnan announcing the continuation of financial aid for critical projects and an expansion of the Design Linked Incentive (DLI) scheme. Speaking at the Semicon India event, Krishnan revealed that critical semiconductor production projects could receive up to 70% of their total cost as incentives, combining central and state contributions, a policy set to persist to strengthen domestic manufacturing.

The DLI scheme, previously limited to startups and MSMEs with grants up to $2 million, will now extend benefits to larger domestic companies, increasing grant amounts and improving access to risk capital. This move aims to foster innovation and scale up India's chip design ecosystem, aligning with Prime Minister Narendra Modi's vision of a new semiconductor mission. The government has already committed around $30 billion in incentives, with 50% central support and 20% from states, an unprecedented level of backing that Krishnan described as unique globally.

The expansion targets critical areas like display fabs and compound semiconductors, with the India Semiconductor Mission (ISM)-2 set to play a pivotal role. However, some industry voices question whether the focus on large firms might overshadow

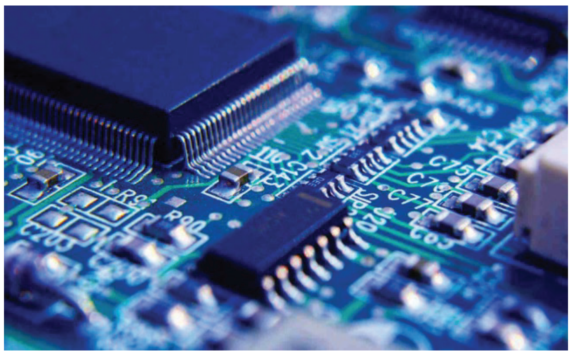

smaller players, while others see it as a necessary step to compete with global leaders like Taiwan and South Korea. As India pushes to become a semiconductor hub, this policy shift could attract more investment, though execution and infrastructure development remain key challenges.

डच टेक दिग्गज ASML भारत के साथ चिप निर्माण साझेदारी की योजना बना रहा है, पीएम मोदी के स्थानीय उत्पादन अभियान के साथ

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को वैश्विक खिलाड़ी बनाने की दिशा में कदम

नई दिल्ली: डच टेक कंपनी ASML होल्डिंग एनवी, जो सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण में अग्रणी है, भारत के साथ साझेदारी की योजना बना रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्थानीय चिप उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। कंपनी के सीईओ क्रिस्टोफ फूक्के ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया शिखर सम्मेलन में कहा कि अगले साल भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाने की योजना है, जो भारत को सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में मजबूत करेगा।

यह कदम भारत की उस महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जहां सरकार ने 2025 के अंत तक घरेलू चिप उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। ASML, जो टॉप चिप निर्माताओं जैसे TSMC और सैमसंग को उन्नत लिथोग्राफी समाधान प्रदान करती है, भारत में कम उन्नत चिप्स के उत्पादन के लिए अपनी मशीनों की पेशकश कर सकती है। इससे भारत को अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों के साथ सेमीकंडक्टर स्वावलंबन की दौड़ में बढ़त मिल सकती है।

हालांकि, वैश्विक व्यापार तनाव और चीन पर निर्यात प्रतिबंधों के कारण ASML के लिए यह कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में निवेश से कंपनी को नई बाजार संभावनाएं मिलेंगी, लेकिन स्थानीय बुनियादी ढांचे और नीतिगत समर्थन की जरूरत होगी। पीएम मोदी ने इस पहल को आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बताया, जो रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा। यह साझेदारी भारत को वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति दिला सकती है।

ग्रामीण भारत में सस्ते प्रीमियम FMCG खरीद में उछाल, शहरी बाजारों को पछाड़ा

बढ़ती आकांक्षाएं और छोटे पैकेज सस्ती पहुंच का कारण

भोपाल: ग्रामीण भारत में सस्ते प्रीमियम तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामानों (FMCG) की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जो शहरी बाजारों को पीछे छोड़ रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों ने 51% की हिस्सेदारी के साथ प्रीमियम FMCG खपत में अग्रणी भूमिका निभाई, जो 2021 के 45% से बढ़ी है। यह बदलाव बढ़ती आकांक्षाओं, सामग्री की बढ़ती खपत और छोटे पैक साइज की उपलब्धता से प्रेरित है।

पारले प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष मयंक शाह ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास सामाजिक मीडिया सहित अधिक समय है, जो ब्रांड जागरूकता को बढ़ाता है। प्रीमियम उत्पादों का ग्रामीण वॉल्यूम ग्रोथ 9% रहा, जो शहरी 6% से अधिक है। पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीमियम FMCG पर औसत खर्च सालाना 11% बढ़ा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 7% रहा। डाबर, जो अपनी आधी से अधिक आय ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त करता है, ने छोटे पैक साइज के प्रीमियम उत्पाद पेश किए हैं, जो ग्राहकों के लिए सस्ती हो गए हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण बाजार, जो जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं, प्रीमियम उत्पादों की मांग को धीरे-धीरे बढ़ाएंगे। हालांकि, शहरी उपभोक्ताओं में जरूरी वस्तुओं पर खर्च कम होकर मनोरंजन और यात्रा पर बढ़ रहा है। यह बदलाव FMCG कंपनियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे पैक और सस्ती कीमतें ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण का कारण बन रही हैं, जो इस क्षेत्र को विकास का नया केंद्र बना सकता है।

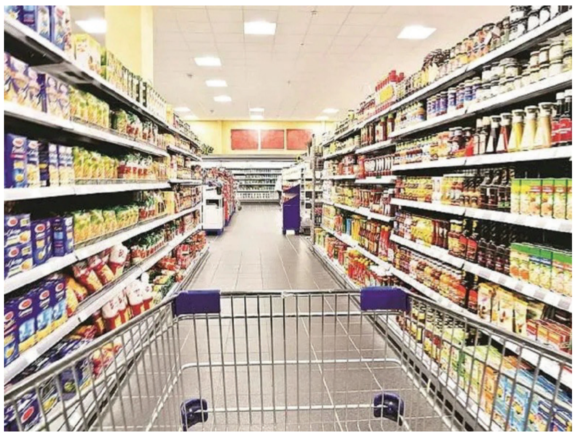

अदानी पावर ने 2032 तक 41 GW थर्मल लक्ष्य निर्धारित किया

ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बड़े निवेश की योजना

भोपाल: भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी अदानी पावर ने 2032 तक अपनी थर्मल बिजली क्षमता को 41 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह घोषणा कंपनी की हालिया निवेश योजना के साथ की गई, जिसमें 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 11 GW क्षमता जोड़ी जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार के 2032 तक 80 GW थर्मल क्षमता वृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी 30 GW जोड़ने की योजना बना रही है।

अदानी पावर ने पहले 18.15 GW से बढ़ाकर 30 GW तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन बढ़ती ऊर्जा मांग और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संतुलन के लिए इसे संशोधित किया गया। कंपनी का कहना है कि यह विस्तार आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित होगा, जो उसके वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। थर्मल पावर संयंत्रों में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए किया जाएगा। यह कदम भारत की 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने में आधारभूत लोड प्रदान करेगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा कर सकती है। दूसरी ओर, कंपनी का दावा है कि यह कदम आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अदानी पावर के इस विस्तार से लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत करेगा। यह परियोजना न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएगी, बल्कि देश की औद्योगिक प्रगति को भी गति देगी।

NTPC Green Energy Launches 25 MW Solar Capacity into Commercial Operation

Boost to Renewable Energy Portfolio Strengthens India's Clean Energy Push

New Delhi: NTPC Green Energy Limited, a subsidiary of India's largest power producer NTPC, has announced the commercial operation of a 25 MW solar capacity, effective September 3, 2025. This milestone enhances the NTPC group's total installed and commercial capacity to 83,366 MW, reinforcing its commitment to renewable energy.

The new solar project, located in Bhuj, Gujarat, is part of a broader 150 MW initiative developed by Ayana Renewable Power Four Private Limited, a subsidiary of a joint venture with ONGC NTPC Green Private. significant step in expanding India's clean energy footprint, aligning with the nation's goal of achieving 500 GW of renewable capacity by 2030.

The announcement follows a regulatory filing by NTPC, highlighting the project's contribution to the group's green energy portfolio. Industry experts view this as a positive signal for sustainable growth, though some caution that reliance on solar must be balanced with energy storage solutions to address intermittency. The project is expected to create jobs and stimulate local economies in Gujarat.with the nation's goal of achieving 500 GW of renewable capacity by 2030.

The announcement follows a regulatory filing by NTPC, highlighting the project's contribution to the group's green energy portfolio. Industry experts view this as a positive signal for sustainable growth, though some caution that reliance on solar must be balanced with energy storage solutions to address intermittency. The project is expected to create jobs and stimulate local economies in Gujarat.

India Targets 107 GW Wind Energy Capacity by 2030, Says Global Wind Energy Council

Ambitious Growth to Boost Jobs and Green Economy

New Delhi: The Global Wind Energy Council (GWEC) has projected that India's wind energy capacity could reach 107 GW by 2030, surpassing the government's target of 100 GW. This optimistic forecast, detailed in the latest GWEC report, highlights a potential doubling from the current 51 GW, driven by state-level Resource Adequacy Plans (RAP) and robust policy support.

The report, unveiled recently, suggests that scaling installations to 15 GW annually could create 1.54 lakh jobs and position India as a global wind manufacturing hub, meeting 10% of worldwide demand. Union Minister Pralhad Joshi emphasized the government's commitment to installing 500 GW of non-fossil capacity by 2030, with wind contributing a quarter of the renewable mix. Industry leaders like Girish Tanti of GWEC India foresee wind powering 20-25% of global electricity by 2030, a trajectory India aims to mirror.

However, challenges remain, including grid infrastructure and policy alignment, with some experts advocating for even higher targets of 121-164 GW based on global assessments. India's total wind potential stands at 1,164 GW, with only 4.5% tapped so far. This growth could unlock economic benefits and support the nation's clean energy transition, though execution will be key to realizing this vision.

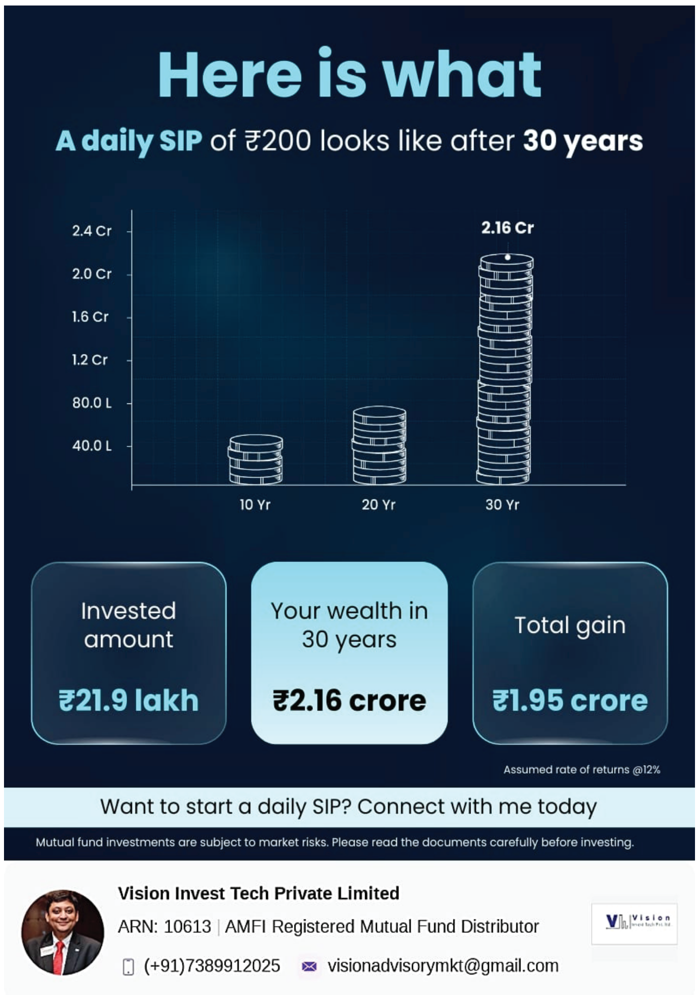

Hindustan Zinc Targets Production of 4 New Metals by 2030: CEO

Diversification Drive to Boost Critical Mineral Supply

Mumbai: Hindustan Zinc Limited, a Vedanta subsidiary and India's leading zinc producer, has unveiled ambitious plans to diversify its portfolio by producing up to four new metals by 2030, as announced by CEO Arun Misra. Speaking at the company's annual general meeting, Misra outlined the strategy to leverage the firm's deep mining expertise to extract critical minerals such as neodymium, tungsten, and potash, alongside exploring gold, platinum, lithium, and graphite.

The initiative builds on Hindustan Zinc'sdominance in zinc, lead, and silver, aiming to address the growing demand for materials vital to electric vehicles, defense, and renewable energy. Misra estimated a four-year timeline two years for exploration and two for setting upmining and smelting plants highlighting the company's readiness to tackle deep-earth and trace mineral challenges. A new subsidiary, Hindmetal Exploration Services, has been formed to spearhead this effort.

This move aligns with India's National Critical Minerals Mission and positions Hindustan Zinc to capitalize on global supply chain shifts, especially amid China's export restrictions on rare earths. However, the plan faces hurdles, including technical complexities and environmental concerns. The company's focus on

sustainable practices and international partnerships could mitigate these risks, potentially making it a key player in India's mineral security.

Glenmark Introduces Generic Cancer Drug in US Market

Affordable Oncology Solution Boosts Access for Patients

Mumbai: Glenmark Pharmaceuticals has launched Eribulin Mesylate Injection, a generic cancer treatment, in the US market through its subsidiary, Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA. Announced recently, this move marks a significant step in providing affordable oncology solutions, with distribution set to begin this month. The drug, a therapeutic equivalent to Eisai Inc.'s Halaven Injection, targets various cancers and is priced to enhance patient access.

The 1 mg/2 mL (0.5 mg/mL) single-dose vials address a market with annual sales of approximately $66.3 million for the reference drug, based on IQVIA data for the 12-month period ending July 2025. Glenmark's President and Business Head for North America, Marc Kikuchi, emphasized the launch as a commitment to expanding the institutional channel with quality, cost-effective alternatives. This milestone reinforces the company's growing presence in the US generics market.

The introduction comes amid rising global demand for affordable cancer treatments, with Glenmark leveraging its R&D capabilities to compete in this space. However, the move also faces scrutiny over potential supply chain challenges and regulatory compliance, given past FDA warnings to the company. Industry analysts view this as a strategic play to capture market share, though its success hinges on consistent quality and distribution efficiency.This launch aligns with India's pharmaceutical sector's global ambitions, potentially benefiting millions of patients while boosting Glenmark's revenue stream.

अर्बन कंपनी का 1,900 करोड़ रुपये का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा; प्राइस बैंड 98-103 रुपये

घरेलू सेवा क्षेत्र में निवेश का नया अवसर

भोपाल: अर्बन कंपनी, जो मोबाइल ऐप-आधारित सौंदर्य और घरेलू सेवा मंच है, 10 सितंबर 2025 को अपने 1,900 करोड़ रुपये के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए सब्सक्रिप्शन खोलेगी। कंपनी ने प्राइस बैंड 98 से 103 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जिसके ऊपरी छोर पर कंपनी का मूल्यांकन 14,790 करोड़ रुपये होगा। यह आईपीओ 10 से 12 सितंबर तक खुला रहेगा, जबकि 9 सितंबर को एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

आईपीओ में 472 करोड़ रुपये का नया शेयर निर्गम और 1,428 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है, जिसमें मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। फंड का उपयोग नई तकनीक विकास, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्यालय किराए और विपणन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स इस प्रक्रिया के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर होंगे।

यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा मांग बढ़ने के साथ कंपनी के विस्तार को दर्शाता है। हाल के वित्तीय वर्ष में कंपनी का राजस्व 1,144 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 38% अधिक है। हालांकि, निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा जैसे जोखिमों पर विचार करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आईपीओ घरेलू सेवा क्षेत्र में निवेश का आकर्षक अवसर हो सकता है, बशर्ते कंपनी अपनी विकास रणनीति को सही ढंग से लागू करे।

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24741	25552	25266	25004	24718	24456	24170	23908
BANK NIFTY	54115	55347	54882	54499	54034	53651	53186	52803
SENSEX	80711	83130	82294	81502	80666	79874	79038	78246
FINNIFTY	25889	26652	26338	26113	25799	25574	25260	25035
MIDCAP	12778	13451	13200	12989	12738	12527	12276	12065
ACC	1830	1947	1913	1872	1838	1797	1763	1722
AXISBANK	1056	1086	1075	1066	1055	1046	1035	1026
ABCAPITAL	281	298	292	286	280	274	268	262
BHARTIARTL	1894	1964	1941	1917	1894	1870	1847	1823
BHEL	213	232	226	220	214	208	202	196
BIOCON	363	388	376	370	358	352	340	334
CDSL	363	388	376	370	358	352	340	334
DATAPATTERN	2469	2765	2681	2575	2491	2385	2301	2195
ESCORTS	3693	4655	4412	4053	3810	3451	3208	2849
EICHERMOTOR	6563	7411	7050	6807	6446	6203	5842	5599
FEDERAL BANK	191	202	198	195	191	188	184	181
GRINFRAPOJECT	1290	1379	1342	1316	1279	1253	1216	1190
HDFCBANK	963	1002	985	974	957	946	929	918
HCLTECH	1420	1538	1507	1464	1433	1390	1359	1316
HINDUNILVR	2628	2837	2793	2711	2667	2585	2541	2459
HAL	4415	4670	4582	4499	4411	4328	4240	4157
HYUNDAI	2535	2714	2637	2586	2509	2458	2381	2330
IOC	140	147	145	142	140	137	135	132
ICICIBANK	1404	1449	1432	1418	1401	1387	1370	1356
INFY	1446	1575	1544	1495	1464	1415	1384	1335
ITC	408	440	432	420	412	400	392	380
KOTAKBNK	1940	2009	1992	1966	1949	1923	1906	1880
LICHOUSING	555	580	573	564	557	548	541	532
LT	3555	3682	3654	3605	3577	3528	3500	3451
LUPIN	1944	2070	2020	1982	1932	1894	1844	1806
MARUTI	14937	15843	15542	15239	14938	14635	14334	14031
M&M	3561	4081	3829	3695	3443	3309	3057	2923
MGL	1285	1405	1370	1327	1292	1249	1214	1171
MAZGAONDOC	2685	2968	2874	2779	2685	2590	2496	2401
PFC	395	420	409	402	391	384	373	366
RECLTD	367	397	384	376	363	355	342	334
RELIANCE	1376	1436	1411	1393	1368	1350	1325	1307
SBIN	807	827	822	814	809	801	796	788
SUNPHARMA	1593	1651	1625	1609	1583	1567	1541	1525
SHRIRAMFINANCE	596	619	607	602	590	585	573	568
TITAN	3660	3887	3813	3737	3663	3587	3513	3437
TCS	3049	3251	3203	3126	3078	3001	2953	2876
TATAMOTORS	694	745	725	710	690	675	655	640
UPL	689	767	750	719	702	671	654	623
VALIENT	361	396	378	370	352	344	326	318
WIPRO	244	262	257	251	246	240	235	229

10 विशाखा मुल्ये को आदित्य बिरला कैपिटल का पांच साल के लिए नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया

नेतृत्व परिवर्तन से कंपनी को मिलेगी नई दिशा

भोपाल: वर्ष 2022 से कंपनी के साथ जुड़ी मुल्ये ने 'वन एबीसी, वन पीएंडएल' रणनीति को लागू कर कंपनी के विकास और लाभप्रदता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में कंपनी ने 4,500 करोड़ रुपये का विकास पूंजी जुटाई और डिजिटल मंच 'एबीसीडी' के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाई। वह आदित्य बिरला मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एबीएमसीपीएल) की बोर्ड में भी शामिल हैं, जो समूह की रणनीतिक दिशा तय करती है।
इससे पहले, मुल्ये ने आईसीआईसीआई बैंक में वरिष्ठ भूमिकाएं निभाईं, जिसमें कार्यकारी निदेशक और समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल हैं। उनके 30 साल के बैंकिंग अनुभव से एबीसीएल को वित्तीय सेवाओं में मजबूती मिलने की उम्मीद है। राकेश सिंह को भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के कार्यकारी निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पांच साल के लिए प्रभावी होगा।
यह नियुक्ति कंपनी के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है, क्योंकि विशाखा मुल्ये की रणनीति से वित्तीय क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद है।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in